

मुख्यमंत्री के निजी सचिव तुलसी कौशिक का हुआ दली राजहरा आगमन



राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार के लिए 30 जून तक आवेदन आमंत्रित

बोमेता। छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्पणा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष खिलाड़ियों/ प्राथिकों/निर्णायिकों को खेल पुरस्कार प्रदान कर राज्य खेल अंतर्करण से सम्मानित किया जाता है। खेल व युवा युवा कल्पणा विभाग ने खेल पुरस्कार के लिए अवेदन 30 जून तक आवेदन मांगा गया है।

यह पुरस्कार गज्ज के लिए उच्च प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों/ प्रशिक्षकों/ निर्णायिकों को प्रदान किये जाते हैं। राज्य खेल अंतर्करण के अंतर्गत सीनियर वर्ग के लिए खिलाड़ियों को शाही कौशल यादव पुरस्कार से अलंकृत किया जाता है जिनके द्वारा जूनीय वर्ष के ग्रीष्म विभागीय में कोई प्रकट किया गया है।

संपादकीय

जा रहा है संदेह

गहराता जा रहा है संदेह

ऐसा पहली बार हुआ कि नीट-यूजी परीक्षा में बैठे 67 छात्रों ने पूरे अंक पा कर पहली रँक हासिल की। ऑल इंडिया स्तर पर प्रथम रँक अब तक एक या दो छात्रों को ही मिलती रही है। इसलिए संदेह गहरा गया है। यह संदेह गहराता जा रहा है कि प्रतियोगी परीक्षाएं धांधली का जरिया बन गई हैं और यह सब कुछ प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है। अनेक राज्यों में पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं से यह शक बनना शुरू हुआ। अब देश के टॉप मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेस टेस्ट (नीट-यूजी) को लेकर खड़े हुए विवाद से यह और गहरा गया है। परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) सवालों के घेरे में है। शक को इससे भी बल मिला कि जिस रोज लोकसभा चुनाव की मतगणना में सारे देश का ध्यान था, एनटीए ने उसी रोज इनहान के नतीजों को जारी करने का फैसला किया। ऐसा पहली बार हुआ कि इस परीक्षा में बैठे 67 छात्रों ने पूरे अंक पा कर पहली रँक हासिल की। ऑल इंडिया स्तर पर प्रथम रँक अब तक एक या दो छात्रों को ही मिलती रही है। एनटीए ने सफाई दी है कि आसान परीक्षा, रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी, दो सही उत्तरों वाला एक प्रश्न और परीक्षा के समय में नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स दिया जाना ऐसे कारण हैं, जिनसे छात्रों को उच्च अंक लाने में सहायता मिली। मगर परीक्षा में शामिल हुए छात्रों के एक बड़े हिस्से को यह स्पष्टीकरण मंजूर नहीं है। वे परीक्षा रद्द कर इसे दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। एनटीए का कहना है कि 1,500 से ज्यादा उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क की समीक्षा करने के लिए चार सदस्यों की कमेटी गठित की गई है, जो एक हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मगर संदेह इतना गहरा है कि ऐसे स्पष्टीकरण से छात्रों एवं समाज के एक बड़े हिस्से को संतुष्ट करने में सफलता नहीं मिली है। आरोप है कि पेपर लीक किया गया। यह मुद्दा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से संबंधित जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने उठाया। उसने मामले की सीबीआई जांच और दोबारा परीक्षा कराने को कहा है। जो हालात हैं, उनके बीच इन मांगों को तुकराना मुश्किल मालूम पड़ता है। अगर ऐसा कर भी दिया गया, तो यह परीक्षा की शुचिता पर संदेह जारी रखने की कीमत पर ही होगा।

विशेष लेख

मध्यप्रदेश में खास रही स्त्री शक्ति की भूमिका

-प्रो.संजय द्विवेदी

मध्यप्रदेश में सभी लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त कर भाजपा ने कठिन समय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बड़ा सहारा दिया है। जिसमें मध्यप्रदेश की महिला मतदाताओं का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव अभियान से ही प्रधानमंत्री मोदी मध्यप्रदेश में सबसे खास चेहरा बने हुए हैं। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा ने मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा था और भारी जनसमर्थन प्राप्त किया। मोदी के मन में मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश के मन में मोदी यह मुख्य नारा था, जिसमें संगठन के परिश्रम ने प्राण फूंक दिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सत्ता में तीसरी बार वापसी एक असाधारण घटना है। भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में अपनी लोकप्रियता और प्रासंगिकता बनाए रखना इतना आसान नहीं होता। भाजपा जैसे दल के लिए जिसने 8 वें दशक में सिर्फ दो लोकसभा सीटों के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ की हो, यह चमत्कार ही है। अनपेक्षित परिणामों के बाद भी केंद्र में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी और एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन है। मध्यप्रदेश वैसे भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के अद्भुत समन्वय से चलने वाला राज्य रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गजों की जुगलबंदी ने जो इतिहास रचा है, उसे लंबे समय तक याद किया जाएगा। इसके अलावा नरेन्द्र सिंह अपनी श्रद्धा के पूर्ण भेंट करता हूं। उहोंने देश के समक्ष बलिदान और देश सेवा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है, परंतु इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि उनका अभिभाषण उन आश्वासनों को पूरा नहीं करता, जिसके आश्वासन कांग्रेस दल ने चुनावों के समय दिया था। उसमें सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों का कोई नया नक्शा नहीं प्रस्तुत किया गया। अभिभाषण में बड़ी गंभीर बातों की उपेक्षा की गयी है। यह तो संतोष की बात है कि भारत ने लोकतंत्रीय प्रणाली को अपनाया है और बहुबली बड़ा चुनाव इस देश में हुआ है, जिसके लिए हम अपने चुनाव आयोग को मुबारकबाद देनी चाहिए। परंतु इस दिशा में कुछ ऐसी भी बातें हुई हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। पदासीन दल ने सरकारी शक्ति का खूब प्रयोग किया है। कांग्रेस के नेता एक ओर तो सांप्रदायिकता और जाति भेद इत्यादि की निंदा करते हैं, परंतु दूसरी ओर, वे सांप्रदायिक वर्गों जैसे ढंग अपनाते रहे हैं। कांग्रेस दल को अपनी विजय पर पूरा नहीं उठना चाहिए।

मैं भारतीय लोकतंत्र के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विदा का प्रणाम प्रस्तुत करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धा के पूल भेट करता हूँ। उन्होंने देश के समक्ष बलिदान और देश सेवा का मुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है, परंतु इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि उनका अभिभाषण उन आश्वासनों को पूरा नहीं करता, जिसका आश्वासन कांग्रेस दल ने चुनावों के समय दिया था। उसमें सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों कोई नया नक्शा नहीं प्रस्तुत किया गया अभिभाषण में बड़ी गंभीर बातों की उपेक्षा की गई है। यह तो संतोष की बात है कि भारत ने लोकतंत्रीय प्रणाली को अपनाया है और बहुबल चुनाव इस देश में हुआ है, जिसके लिए हमें अपने चुनाव आयोग को मुबारकबाद देनी चाहिए। परंतु इस दिशा में कुछ ऐसी भी बातें हुई हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। पदासीन दल ने सरकारी शक्ति का खुब प्रयोग किया है। कांग्रेस के नेता एक ओर तो सांप्रदायिकता और जाति भेद इत्यादि की निंदा करते हैं, परंतु दूसरी ओर, वे सांप्रदायिक वर्गों जैसे ढंग अपनाते रहे हैं। कांग्रेस दल को अपनी विजय पर पूल नहीं उठना चाहिए।

लक्ष्मी मळू सिंघवी

कई मामलों में नाकाम रह गई सरकार

बल्कि उसे चुनावों में जो कमियां रह गई हैं, उन पर विचार करना चाहिए, ताकि भविष्य में भारत में लोकतंत्र मजबूत हो सके। इस बारे में मेरा मत यह है कि संसदीय प्रजातंत्र प्रणाली के लिए विरोधी दल का होना जरूरी है। एक सक्रिय विरोधी दल के बिना प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता। यह भी बड़ी खेदजनक बात है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश में सर्वत्र विद्यमान भ्रष्टाचार का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इसे दूर करने का आश्वासन भी नहीं दिया गया। मेरा कहना तो यह है कि सरकार इसे रोकने में बिल्कुल असफल रही है। इस बुराई को दूर किया जाना बहुत ही आवश्यक है, इसके बिना देश प्रगति की ओर नहीं बढ़ सकता। देश के लिए एक स्वच्छ, ईमानदार तथा सकुशल प्रशासन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विभिन्न राज्यों में चौकसी समितियां बनाई जानी चाहिए तथा प्रक्रियाओं को कड़ा बनाया जाना चाहिए। नमूने के तौर पर किसी भी राज्य में राजनीति में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संपत्ति की जांच की जानी चाहिए। पंजाब और राजस्थान में तो इस प्रकार की जांच की बहुत ही आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सरकारी कामों में जो लालपीताशाही का बोलबाला हो रहा है, उसे भी कम किया जाए। इससे भी काम की बहुत हानि

होती है। अर्थिक समस्या को हल करने के बारे में भी अभिभाषण में कोई विशेष संकेत नहीं है। इस दिशा में प्रगतिशील दृष्टिकोण का नितांत अभाव है। समाजवाद का नाम लेकर ही सारे अवगुणों और दोषों को छिपाने का यत्न किया जाता है। मेरा निवेदन है कि हमें इस सरकारी पूँजीवाद को समाजवाद का दरजा नहीं देना चाहिए। स्थिति में सुधार के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। सरकारी उपक्रमों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि जितनी फिजूलखर्चों वहां होती है, उतनी उन गैर-सरकारी उपक्रमों में नहीं होती है, जिनका निरंतर विरोध किया जाता है। उनकी मजदूरी व्यवस्था तथा उत्पादन व्यय गैर-सरकारी संस्थानों से बहुत अधिक है और कोई वाद श्लाघा योग्य नहीं है। हमें व्यावहारिक रूप में समाजवाद का प्रभाव देखना चाहिए व समाजवाद के नाम पर चल रहा भ्रष्टाचार रोकना होगा। इसके अतिरिक्त आज एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है बेरोजगारी, जिसे सरकार हल नहीं कर सकी है। स्वयं सरकार की ओर से भी इस बात को स्वीकार किया गया है। एक सक्रिय विरोधी दल के बिना प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता। यह भी बड़ी खेदजनक बात है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश में सर्वत्र विद्यमान भ्रष्टाचार का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इसे दूर करने का आश्वासन भी नहीं दिया गया। मेरा कहना तो यह है कि सरकार इसे रोकने में बिल्कुल असफल रही है। इस बुराई को दूर किया जाना बहुत ही आवश्यक है, इसके बिना देश प्रगति की ओर नहीं बढ़ सकता। देश के लिए एक स्वच्छ, ईमानदार तथा सकुशल प्रशासन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विभिन्न राज्यों में चौकसी समितियां बनाई जानी चाहिए तथा प्रक्रियाओं को कड़ा बनाया जाना चाहिए। नमूने के तौर पर किसी भी राज्य में राजनीति में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संपत्ति की जांच की जानी चाहिए। पंजाब और राजस्थान में तो इस प्रकार की जांच की बहुत ही आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सरकारी कामों में जो लालपीताशाही का बोलबाला हो रहा है, उसे भी कम किया जाए। इससे भी काम की बहुत हानि होती है। अर्थिक समस्या को हल करने के बारे में भी अभिभाषण में कोई विशेष संकेत नहीं है। शायद सरकार यह समझने लग गई है कि यह प्रश्न हल नहीं हो सकता, परंतु इसके प्रति अधिक देर उदासीन नहीं रहा जा सकेगा। इस समस्या के साथ शिक्षित बेरोजगारों की समस्या भी संबंद्ध है। अतः इससे देश में क्रांति हो सकती है, इसे बहुत संतोषजनक ढंग से हल करना ही होगा।

गठबंधन सरकार से भी उम्मीदें बेशुमार

आलोक जोशी

भारत एक कृष्ण प्रधान दश है, जिसका आधिकत आबादी गांवों में बसती है। दसियों साल से स्कूल वे निबंधों में कैद यह पर्कि अब शायद वापस राजनीति वे केंद्र में लौट रही है और इसके साथ ही अर्थनीति पर भी इसकी छाप स्वाभाविक है। दूसरी ओर, बढ़ते आबादी पर लगाम कसने की नाकाम कोशिश के बारे उसी आबादी को डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानि जनसांख्यिकीय लाभांश बताने का हैंगओवर भी सामने आ चुका है। इसका अर्थ है, सरकार की प्राथमिकताओं में रोजगार का इंतजाम सबसे बड़ी प्राथमिकता बन सकता है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का अधिकृत शुरुआत से पहले ही सौ दिनों के एजेंडे पर काम चालू हो चुका था, मगर सरकार के अहम सहयोगी इन एजेंडों को कितना पटरी पर रहने देंगे, यह सबाल बड़ा हो चुका है। यहां हिसाब लगाना जरूरी है कि जीडीपी में बढ़त की रफ्तार आठ मीसदी से ऊपर जाने की खुशखबरी आने के ठीक बाद कहीं उस प्रेरणे का लगाने का डर तो नहीं पैदा होगा? खासकर, यदि देखते हुए कि पिछले कार्यकाल के मुकाबले इस बारे सहयोगी दलों की गिनती कम होने के बावजूद उनका अहमियत बढ़ चुकी है। जनता दल (यूनाइटेड) वे मुखिया नीतीश कुमार और तेलुगू देशम पार्टी वे चंद्रबाबू नायडू की तरफ से अपने-अपने राज्यों के लिए विशेष दर्जे की मांग तो स्वाभाविक है, पर क्या मोदी सरकार के महत्वपूर्ण आर्थिक एजेंडों या आर्थिक सुधारों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोई मांग इनके तरफ से आ सकती है? अलग-अलग विचारों वे बावजूद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, दोनों ही आर्थिक और प्रशासनिक मोर्चे पर सुधार व विकास की राजनीति के लिए ही जाने जाते हैं। यानी, इनकी तरफ से आर्थिक मोर्चे पर किसी बड़ी अडचन की आशंका नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे, भारत में बहुत ब



आर्थिक सुधार ऐसी सरकारों के दौर में हुए हैं, जब या तो मिली-जुली सरकारें थीं या पिछ बाहरी समर्थन पर टिकी सरकार देश चला रही थी। साल 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत या अर्थव्यवस्था को खोलने का काम ही पीछी नरसिंहराव सरकार ने किया था, जिसे संख्या-बल के कारण एक कमज़ोर सरकार माना जाता था। इसी तरह, एच डी डेवेंगोड़ा और इंद्रदेव कुमार गुजराल की संयुक्त मोर्चा सरकारों ने आयकरों की स्लैब घटाकर तीन करने का काम और दूरसंचार नियामक ट्राई (टीआरएआई) की स्थापना जैसे बड़े फैसले किए। दूरसंचार, पेंशन, सरकारी घाटे पर लगाम कसने की व्यवस्था, बिजली और बीमा क्षेत्र के अनेक बड़े सुधार अटल बिहारी वाजपेयी की उस सरकार ने किए, जिसे अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं था मनमोहन सिंह ने भी यूपीए के दौर में मनरेगा, खाद्य सुरक्षा कानून, भूमि अधिग्रहण कानून और पेट्रोलियम उत्पादों को बाजार के हवाले करने जैसे बड़े फैसले किए। वैसे, मोदी सरकार के भी पहले कार्यकाल में जीएसटी लागू करने जैसा बड़ा काम हुआ, जिसमें सारी राज्य सरकारों को राजी करना जरूरी था। हालांकि, कई

बार पूर्ण बहुमत वाली सरकारें भी वह नहीं कर पाई, जो वह करना चाहती थीं, जैसे- मोदी सरकार में कृषि कानूनों की वापसी। यह जरूर है कि गठबंधन में सरकारें ऐसे काम नहीं कर पातीं, जिनसे किसी के नाराज होने का डर हो, पर ऐसे काम तेज हो सकते हैं, जिनका फयदा साफ दिखता हो, या जो गठबंधन में शामिल सभी या अधिकतर पार्टियों के एजेंडे से मेल खाते हों। आज का हाल देखें। बुनियादी ढांचे में सुधार, सड़क, रेल, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना- इसमें भला कौन सी बाधा आ सकती है? श्रम कानूनों में सुधार या बदलाव पर विवाद हो सकता है, लेकिन उसके बिना भी भारत तेज विकास कर रहा है। वास्तव में, इस वक्त हालात जितने अनुकूल दिखते हैं, वैसे शायद पहले कभी नहीं रहे। अर्थव्यवस्था में बढ़त की रफ्तार 8.2 प्रतिशत पर पहुंच चुकी है। रिजर्व बैंक ने भारत सरकार को उम्मीद से दोगुना लाभांश दिया है। जीएसटी वसूली ने रिकॉर्ड बनाती जा रही है। आयकर व कॉरपोरेट टैक्स के मोर्चे पर कमाई बढ़ती जा रही है। सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने का लक्ष्य भले पूरा न हो,

